ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI-110011

Priyanka Gandhi Vadra
General Secretary

16 अप्रैल 2020

सेवा में,
श्री योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

विषय- कोरोना आपदा से प्रभावित आम जन को राहत देने के संदर्भ में

मुख्यमंत्री महोदय,

आशा है कि आप सकुशल होंगे। कोरोना महामारी ने आज ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है।

मुख्यमंत्री जी कोरोना आपदा की वजह से कई ऐसे आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जन को बहुत राहत मिलेगी-

1. किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कटाई कैसे होगी? आपने कम्बाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है परंतु अभी तक कम्बाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत हैं। आपको मालूम होगा कि ज्यादातर इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं। उनके आने की व्यवस्था की जाए। सही सूचना के अभाव में और जुर्माने के डर से किसान रात-बिरात गेहूं काट रहे हैं।

2. गन्ना किसानों का बकाया तत्काल भुगतान करें साथ ही साथ आगामी फसल की खरीद की गारंटी करें।

3. विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर ओलवृष्टि और बेमौसम बारिश की मार पड़ी थी। आपने मुआवजा देने की भी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कृपया ओलावृष्टि और बारिश से हुई फसलों की बर्बादी का मुआवजा सभी किसानों को तुरंत दिया जाए।

4. कोरोना महामारी अपने साथ एक आर्थिक तबाही भी लेकर आई है। उत्तर प्रदेश का काँच उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, बुनकरी, फ़र्नीचर उद्योग, चमड़े का उद्योग, होजरी उद्योग, डेयरी, मिट्टी बर्तन उद्योग, फिशरी-हेचरी उद्योग, अन्य घरेलू उद्योग सभी को तेज झटका लगा है। प्रदेश के लाखों बुनकरों की हालत अत्यंत खराब है। देश और प्रदेश में एक आर्थिक ठहराव की स्थिति पैदा हो गई है। मजदूरों और छोटे उद्योगों की स्थिति बहुत ही खराब है। आपसे गुजारिश है कि प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण के जाने माने विशेषज्ञों की एक **'आर्थिक पुनर्निर्माण टास्कफोर्स'** गठित की जाए। इस आपदा के साथ आने वाली आर्थिक सुनामी से मुकाबला करने के लिए इस टास्कफोर्स का काम आर्थिक पुनर्निमाण का रास्ता तैयार करना होगा।

5. अभी भी बहुत मजदूर परिवारों को राशन व नकदी की किल्लत है। काफी मजदूरों का पंजीकरण न होने से उनको किसी भी राहत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बिना पंजीकृत मजदूरों को भी आर्थिक मदद की गारंटी की जाए। कई जगह राशन न मिलने की शिकायतें आ रहीं हैं। कृपया बिना राशनकार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी की जाए। आपसे निवेदन है कि राशन में चावल के साथ गेंहू, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए।

6. सक्रिय मनरेगा मजदूरों को फ्री में राशन मिल रहा है, यह सराहनीय पहल है किंतु उनको कोई आर्थिक राहत नहीं मिली है। मनरेगा मजदूरों के लिए आपके द्वारा घोषित 611 करोड़ रुपया उनका पिछला बकाया ही था। आपसे निवेदन मनरेगा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए।

महोदय, इस आपदा के समय आम जनों को सहूलियत देकर प्रदेश में इस आपदा के असर को कम करने में इन कदमों पर गौर करना बहुत जरुरी है।

जय हिंद

भवदीय

प्रियांका गांधी वाद्रा